(ख) अब तक जारी किए गए रसोई गैस कनेक्शनों की संख्या 7023 है ।

(ग) 15.5.98 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूचीबद्ध व्यक्तियों की संख्या 560 है।

(घ) 31.3.1998 तक तैयार की गई सम्पूर्ण प्रतीक्षा सूची सूचना पत्र भेज कर पहले ही पूरी कर ली गई है। सूचना पत्र की वैधता 60 दिन के लिए है। वैधता अवधि के भीतर डिस्ट्रीब्यूटर से सम्पर्क न करने वाले प्रतीक्षा सूचीबद्ध व्यक्तियों का पंजीकरण निरस्त लिया जाता है। परन्तु इसे क्षेत्र अधिकारी/एरिया प्रबंधक द्वारा ग्राहक की ओर से अभ्योवेदन पर पुनः वैध किया जा सकता है।

(ड़) केवल एक शिकायत मिली थी। इस मामले में वितरक ने पंजीकरण की परिपक्वता की सूचना देते हुए एक पंजीकृत पत्र भेजा है। उक्त पत्र इन टिप्पणियों के साथ लौटा दिया गया था कि "पत्र इस ब्रांच कार्यालय के अधीन ऐसा कोई भी प्रेषिती न होने के कारण लौटाया जाता हैं"। अतः उक्त शिकायत गैस कनेक्शन देने से इन्कार के कारण नहीं है बल्कि कुकिंग कराते समय दिए गए अपर्याप्त पते के कारण है।

बिहार में पेट्रोल पम्पों का आबंटन

236. **श्री जनार्दन यादव** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान बिहार में कितने पेट्रोल पम्प आबंटित किए गए हैं;

(ख) आबंटित पेट्रोल पम्पों में से कितने स्थानों पर उन्हें लगाया जा चुका है; और

(ग) क्या सरकार बिहार के बांका जिले में बांका से बेलहर के बीच सड़क पर एक भी पेट्रोल पम्प नहीं है और क्या सरकार यह देखते हुए कि उस सड़क पर एक भी पेट्रोल पम्प नहीं है, बांका और बेलहर के बीच एक पेट्रोल पम्प आबंटित करने का विचार रखती है और यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान बिहार राज्य में 49 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें आबंटित की गई थीं। उपयोक्त में से 45 खुदरा बिक्री केन्द्र चालू हो गए है।

(ग) बांका तथा बेलहर रोड़ के बीच कोई पेट्रोल पंप नहीं है। न्यून संभाव्यता के कारण वर्तमान में बांका तथा बेलहर के बीच की सड़क पर खुदरा बिक्री केन्द्र विकसित करने के लिए प्रस्ताव नहीं है।

बिहार में दरभंगा में पेट्रोल पम्पों द्वारा रसीदों का जारी न किया जाना

237. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि बिहार में दरभंगा के सभी पेट्रोल पम्प सामान खरीदने पर रसीद नहीं देते हैं,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पेट्रोल पंपों की जांच करा कर उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) दरभंगा (बिहार)में पेट्रोल पंपों पर वस्तुओं की खरीद पर रसीद जारी नहीं करने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

Steps to increase Oil Production in the Country

238. SHRI SITARAM KESRI: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a)the steps being taken by Government to increase the production of oil indigenously with a view to saving the outgo of precious foreign exchange on oil imports;

(b)the quantity of oil imported and the foreign exchange involved during the last two years; and

(c)how far the steps taken by Government to increase indigenous production have yielded results?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI SANTOSH KUMAR GANGWAR): (a) Various steps taken by the Government to increase the production of crude oil are:—

(i) Better long-term reservoir management of the Bombay High Oil fields through closure of high GOR and high water cut wells.

(ii) Implementation of specialised technologies such as extended reach drilling, horizontal and drain hole drilling, infill drilling, re-distribution of water injection, possible application of air injection etc.

(iii) The services of international experts have been hired in the areas of formation evaluation, reservoir engineering, workover and stimulation, drilling and well completion especially for ERD, horizontal, multilateral & drain hole drilling.

(iv) Plans for improved oil recovery from major field have been drawn up by ONGC. Timely and successful implementation of inputs like water floods optimization, commencement and optimization of artificial lift, profile modification for improved water floods conformance, water alternative gas injection, gas injection, EOR pilots etc. are expected to off-set expected shortfall in production from Bombay High.

(v) 3-D seismic surveys for better understanding of the oil fields.

(vi) Encouraging the participation of private/Joint Ventures in oil exploration and development.

(b) The details of the quantity of crude oil imported and the foreign exchange spent are:—

Year	Quantity (MMT)	Value (Million US$)
1997-97	33.9	5135.00
1997-98*	34.5	4251.50

*Provisional

(c) The results of the various steps taken to increase production can not be quantified in the short term. However, the various measures taken have been successful in checking the declining trend in production.

महाराष्ट्र में गैस एजेंसियां

239. **श्री सुर्यभान पाटील वहाडणे** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र के प्रत्येक जिले में गैस एजेंसियों तथा उनके ग्राहकों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) प्रत्येक गैस एजेंसी में प्रतीक्षा सूची में शामिल लोगों की संख्या कितनी है; और

(ग) उन्हें कब तक गैस के कनैक्शन उपलब्ध करा दिए जाएंगे?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) 1.10.1997 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र में 713 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप थी, जिनकी ग्राहक संख्या 50.93 लाख थी तथा 15.44 व्यक्ति प्रतीक्षाअ सूची में थे।

(ग) आवेदकों को यथाशीघ्र एल पी जी कनेक्शन जारी करने के प्रयास लगातार जारी है। प्रतीक्षा सूचीबद्ध व्यक्तियों को कनेक्शन उनकी वरिष्ठता के अनुसार चरणबद्ध तरीके से दिए जाते हैं और आशा है कि सम्पूर्ण प्रतीक्षा सूची को 2001-2 तक पूरी कर लिया जाएगा।

महाराष्ट्र के आदिवासी जिलों में प्राथमिकता आधार पर रसोई गैस के कनैक्शनों का आबंटन

240. **सूर्यभान पाटील बहाडाणे** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बतान एकी कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र के आदिवासी जिलों में प्राथमिकता आधार पर रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध कराने की कोई योजन है; और

(ख) यदि हां, तो उसका विस्तृत ब्यौरा क्या है तथा उपरोक्त जिलो में आपूर्ती की जा रही गैस की मात्रा कितनी है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्र (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) महाराष्ट्र राज्य सहित देश में जनजातीय जिलों में प्राथमिकता के आधार पर एल पी जी प्रदान करने की कोई योजना नही है। जनजातीय जिलों को भी सामान्य नीति के अंतर्गत शामिल किया जाता है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।